संख्या-52/2023/1264/18-2-2023-18-2099/418/2023

प्रेषक

प्रांजल यादव
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ0प्र0,
कानपुर।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 20 अक्टूबर, 2023

विषयः- प्रदेश में भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामान्य वित्तीय नियम (जी0एफ0आर0)-2017 में किये गये कतिपय संशोधनों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-8/2023/ए-1-01 भा0स0/ए-1/दस-2023-10(13)/2016, दिनांक 22-9-2023 (प्रति संलग्न), का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेन्ट आफ एक्सपेंडिचर प्रोक्योरमेन्ट पालिसी डिवीजन, भारत सरकार के पत्र दिनांक 11-9-2023 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

2- अवगत कराना है कि भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य वित्तीय नियम (जी0एफ0आर0)-2017 के नियम-144(xi) में प्रविष्टि के संदर्भ में कतिपय संशोधन करते हुये वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेन्ट आफ एक्सपेंडिचर प्रोक्योरमेन्ट पालिसी डिवीजन, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-एफ-7/10/2021 पी0डी0पी0, दिनांक 11-9-2023 के साथ कार्यालय ज्ञाप संख्या-एफ-7/10/2021 पी0डी0पी0, दिनांक 23-2-2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-एफ-7/10/2021 पी0डी0पी0(1), दिनांक 23-2-2023 सभी राज्यों को प्रेषित करते हुये आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य वित्तीय नियम (जी0एफ0आर0)-2017 में वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेन्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आफ एक्सपेंडिचर प्रोक्योरमेन्ट पालिसी डिवीजन, भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन विषयक उक्त पत्रों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

प्रांजल यादव
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 उप सचिव, वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेन्ट आफ एक्सपेंडिचर प्रोक्योरमेन्ट पालिसी डिवीजन, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 11-9-2023 के संदर्भ में।
2 प्रभारी, जेम सेल, लखनऊ।
3 समस्त संयुक्त आयुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।
4 समस्त उपायुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।
5 वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-8/2023/ए-1-01भा0स0/ए-1/दस-2023-10(13)/2016, दिनांक 22-9-2023 के क्रम में।
6 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

पुष्पेन्द्र सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 8/2023/ए-1-01 भा0स0 /ए-1-/दस-2023-10(13)/2016

प्रेषक,

पूर्ण देव उपाध्याय,
विशेष सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 22 सितम्बर,2023

विषय - भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से खरीद हेतु जी.एफ.आर. 2017 में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री अनिल कुमार, उप सचिव, भारत सरकार वित्त मंत्रालय डिपार्टमेन्ट ऑफ एक्सपेंडिचर प्रोक्योरमेन्ट पॉलसी डिवीजन का पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2023, जो समस्त राज्यों के मुख्य सचिवों को सम्बोधित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017 के नियम 144 (xi) में प्रविष्टि के सन्दर्भ में कतिपय संशोधन करते हुये भारत सरकार वित्त मंत्रालय डिपाटमेन्ट आफ एक्सपेंडिचर प्रोक्योरमेन्ट पॉलसी डिवीजन द्वारा कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23-02-2023 और सार्वजनिक खरीद आदेश संख्या-4 दिनांक 23-02-2023 निर्गत किया गया है । उक्त पत्र में उल्लिखित आदेशों को राज्यों में भी परिचालित कराये जाने का अनुरोध किया गया है ।

3- अत: भारत सरकार वित्त मंत्रालय डिपार्टमेन्ट आफ एक्सपेंडिचर प्रोक्योरमेन्ट पॉलसी डिवीजन का पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2023 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नक-यथोपरि ।

भवदीय,
पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव

संख्या 8/2023/ए-1-01भा0स0/दस-2023 10(13)/2016 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत-

(1) अपर/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को इस आशय से संदर्भित है कि वह भारत सरकार वित्त मंत्रालय डिपाटमेन्ट आफ एक्सपेंडिचर प्रोक्योरमेन्ट पॉलसी डिवीजन के पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगट आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।

(2) श्री अनिल कुमार, उप सचिव, भारत सरकार वित्त मंत्रालय डिपार्टमेन्ट ऑफ एक्सपेंडिचर प्रोक्योरमेन्ट पॉलसी डिवीजन का पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2023 के सन्दर्भ में प्रेषित।

आज्ञा से,
पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

20-1-01 आ0व्य0/सं0-2023

No.F.7/10/2021-PPD
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Procurement Policy Division
******

ACS(Finance)

502, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi.
06.09.2023

No. 30505 /MS/GI/2023

11/9/2023
(अमृता सानी)
प्रमुख स्टाफ आफिसर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Restrictions on procurement from bidders from a country or countries or class or countries on grounds of defence of India

Reference is invited towards Government of India's OM No. F.6/18/2019-PPD dated 23.07.2020 and Public Procurement Orders 1, 2 and 3 (issued thereunder) regarding insertion of Rule 144 (xi) of GFRs, 2017 to provide for restrictions on procurement from bidders from a country or countries or class or countries on grounds of defence of India or matters directly or indirectly related thereto, including national security. These directions were also issued on 23.07.2020 under Article 257(1) of the Constitution of India with a request to State Governments to implement these Orders.

2. Further, in supersession of above said orders, Government of India has amended Rule 144 (xi) of General Financial Rules (vide OM No. F.7/10/2021-PPD dated 23.02.2023) and issued Public Procurement Order No. 4 (vide OM No. F.7/10/2021-PPD (1) dated 23.02.2023), (copies enclosed). The amended Orders were also circulated to all State Governments on 06.03.2023 for implementation.

3. It is again requested that the said directions should be complied with by all State Governments.

सं0-2986/आर्थ/सा0/23

Encls: as above.

संसं (PB)/G-I

(Anil Kumar)
Deputy Secretary (Procurement Policy)
Tel.24627920
Email: anil.kumar14@nic.in

/शु
(दीपक कुमार)
वित्त एवं वित्त आयुक्त, संस्थागत वित्त
एवं वाह्य सहायतित परियोजना विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

Chief Secretaries of all the State Governments

अनुभाग अधिकारी

सूचना-1

15/9/23

15/9/23

(दिनेश बाबू)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

Restrictions on procurement from bidders from a country or countries or class or countries on grounds of defence of India

From : Anil Kumar <anil.kumar14@nic.in> Mon, Sep 11, 2023 01:16 PM

Subject : Restrictions on procurement from bidders from a country or countries or class or countries on grounds of defence of India 3 attachments

To : Dr K. S. Jawahar Reddy, IAS <cs@ap.gov.in>, Dharmendra <cs-arunachal@nic.in>, Chief Secretary Bihar <cs-bihar@nic.in>, Chief Secretary Office <csoffice.cg@gov.in>, Puneet Kumar Goel IAS Chief Secretary <cs-goa@nic.in>, chiefsecretary@gujarat.gov.in, Sanjeev Kaushal, IAS <cs@hry.nic.in>, Prabodh Saxena <cs-hp@nic.in>, Shri Sukhdev Singh <cs-jharkhand@nic.in>, cs@karnataka.gov.in, DR VENU V IAS <chiefsecy@kerala.gov.in>, Iqbal Singh Bains <cs@mp.nic.in>, cs@maharashtra.gov.in, cs-manipur <cs-manipur@nic.in>, cso-meg <cso-meg@nic.in>, cs miz <cs_miz@rediffmail.com>, Jan e Alam, Chief Secretary Nagaland <csngl@nic.in>, Shri Pradeep Kumar Jena <csori@nic.in>, Chief Secretary, Punjab <cs@punjabmail.gov.in>, csraj@rajasthan.gov.in, Vijay Bhushan Pathak <cs-skm@hub.nic.in>, cs@tn.gov.in, CS Telangana <cs@telangana.gov.in>, cs-tripura <cs-tripura@nic.in>, CHIEF SECRETARY GoUP <csup@nic.in>, chief secretary <cs-uttarakhand@nic.in>, PABAN KUMAR BORTHAKUR, IAS <cs-assam@nic.in>, Shri H K Dwivedi <cs-westbengal@nic.in>

Cc : Sanjay Aggarwal <sanjay.aggarwal68@nic.in>, KANWALPREET <kanwal.irss@gov.in>, Sher Bahadur SO <sher.bahadur@nic.in>, Sudesh Kumar <sudesh.kumar85@gov.in>, Anish Kumar <anish.kumar18@gov.in>

Madam/Sir,

Please find OM No. 7/10/2021 - PPD dated 11.09.2023

Regards,

Anil Kumar
Deputy Secretary-PPD,
Department of Expenditure
Ministry of Finance
Lok Nayak Bhawan, New Delhi

OM No. 7 10 2021 - PPD dated 11.09.2023.pdf
57 KB

Amendment to Rule 144(xi) of the General Financial Rules (GFRs), 2017.pdf
77 KB

Order (Public Procurement No. 4) - Restrictions under Rule 144(xi) of the General Financial Rules (GFRs), 2017.pdf
1 MB

No.F.7/10/2021-PPD
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Procurement Policy Division
264-C, North Block, New Delhi.
23.02.2023.

Office Memorandum

Subject: Amendment to Rule 144(xi) of the General Financial Rules (GFRs), 2017.

Rule 144 of the GFRs, 2017 titled 'Fundamental principles of public buying,' had been amended by inserting sub-rule (xi) vide Department of Expenditure (DoE) OM No. F.6/18/2019-PPD dated 23.07.2020. It has now been decided to amend the Rule 144(xi) as under:

Notwithstanding anything contained in these Rules, Department of Expenditure may, by order in writing, impose restrictions, including prior registration and/ or screening, on procurement from bidders from, or bidders having commercial arrangements with an entity from, a country or countries, or a class of countries, on grounds of defence of India, or matters directly or indirectly related thereto including national security; no procurement shall be made in violation of such restrictions.

23/02/2023

(Kanwalpreet)
Director(PPD)
Tel.No. 2309 3811; email: kanwal.irss@gov.in

To

1. Secretaries of all Ministries/ Departments of Government of India.
2. Chief Secretaries/ Administrators of Union Territories/ National Capital Territory of Delhi.

No.F.7/10/2021-PPD (1)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Procurement Policy Division
264-C, North Block, New Delhi.
23.02.2023.

Order (Public Procurement No. 4)

Subject: Restrictions under Rule 144(xi) of the General Financial Rules (GFRs), 2017.

Attention is invited to Order (Public Procurement No. 1) issued vide F.6/18/2019-PPD dated 23.07.2020, Order (Public Procurement No. 2) issued vide F.6/18/2019-PPD dated 23.07.2020, Order (Public Procurement No. 3) issued vide F.6/18/2019-PPD dated 24.07.2020, Office Memorandum (OM) No. F.18/37/2020-PPD dated 08.02.2021, OM No. F.12/1/2021-PPD(Pt.) dated 02.03.2021 and OM No. F.7/10/2021-PPD dated 08.06.2021. In this regard, the following is hereby ordered under Rule 144(xi) (as amended vide OM No. F.7/10/2021-PPD dated 23.02.2023) on the grounds stated therein, in supersession to all of the above mentioned Orders/ clarifications:

Requirement of registration:

2. Any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in any procurement whether of goods, services (including consultancy services and non-consultancy services) or works (including turnkey projects) only if the bidder is registered with the Competent Authority, specified in **Annexure I**.

3. Any bidder (including an Indian bidder) who has a Specified Transfer of Technology (ToT) arrangement with an entity from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in any procurement whether of goods, services (including consultancy services and non-consultancy services) or works (including turnkey projects) only if the bidder is registered with the Competent Authority, specified in **Annexure I**.

4. The requirement of registration for cases covered by paragraph 2 above has been applicable since 23.07.2020. The requirement of registration for bidders covered by paragraph 3 above will be applicable for all procurements where tenders are issued/ published after 01.04.2023.

5. In tenders issued after 23.07.2020 or 01.04.2023, as the case may be, the provisions of requirement of registration of bidders and of other relevant provisions of this Order shall be incorporated in the tender conditions.

Applicability:

6. Apart from Ministries/ Departments, attached and subordinate bodies, notwithstanding anything contained in Rule 1 of the GFRs 2017, the Order shall also be applicable

a) to all Autonomous Bodies;

b) to all public sector banks and public sector financial institutions;

c) to all Central Public Sector Enterprises;

d) to all procurement in Public Private Partnership projects receiving financial support from the Government or public sector enterprises/ undertakings; and

e) Union Territories, National Capital Territory of Delhi and all agencies/ undertakings thereof.

7. This order will not be applicable for cases falling under **Annexure II**.

Definitions:

8. "*Bidder*" for the purpose of the Order (including the term 'tenderer', 'consultant' 'vendor' or 'service provider' in certain contexts) means any person or firm or company, including any member of a consortium or joint venture (that is an association of several persons, or firms or companies), every artificial juridical person not falling in any of the descriptions of bidders stated hereinbefore, including any agency, branch or office controlled by such person, participating in a procurement process.

9. "*Tender*" for the purpose of the Order will include other forms of procurement, except where the context requires otherwise.

10. *"Transfer of Technology"* means dissemination and transfer of all forms of commercially usable knowledge such as transfer of know-how, skills, technical expertise, designs, processes and procedures, trade secrets, which enables the acquirer of such technology to perform activities using the transferred technology independently. (Matters of interpretation of this term shall be referred to the Registration Committee constituted by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, and the interpretation of the Committee shall be final.)

11. *"Specified Transfer of Technology"* means a transfer of technology in the sectors and/ or technologies, specified in paragraph 15, occurring on or after 23.07.2020.

12. *"Bidder (or entity) from a country which shares a land border with India"* for the purpose of the Order means

(a) An entity incorporated, established or registered in such a country; or

(b) A subsidiary of an entity incorporated, established or registered in such a country; or

(c) An entity substantially controlled through entities incorporated, established or registered in such a country; or

(d) An entity whose beneficial owner is situated in such a country; or

(e) An Indian (or other) agent of such an entity; or

(f) A natural person who is a citizen of such a country; or

(g) A consortium or joint venture where any member of the consortium or joint venture falls under any of the above

13. *Beneficial owner* for the purposes of Para 12 (d) will be as under:

(i) In case of a company or Limited Liability Partnership, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person(s), has a controlling ownership interest or who exercises control through other means.

Explanation:-

a. "Controlling ownership interest" means ownership of, or entitlement to, more than twenty-five per cent of shares or capital or profits of the company;

b. "Control" shall include the right to appoint the majority of the directors or to control the management or policy decisions, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements;

(ii) In case of a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s) who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of entitlement to more than fifteen percent of capital or profits of the partnership;

(iii) In case of an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of or entitlement to more than fifteen percent of the property or capital or profits of such association or body of individuals;

(iv) Where no natural person is identified under (i) or (ii) or (iii) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing official;

(v) In case of a trust, the identification of beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen percent or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.

14. "*Agent*" for the purpose of the Order is a person employed to do any act for another, or to represent another in dealings with third persons.

[Note:

i. A person who procures and supplies finished goods from an entity from a country which shares a land border with India will, regardless of the nature of his legal or commercial relationship with the producer of the goods, be deemed to be an Agent for the purpose of this Order.

ii. However, a bidder who only procures raw material, components etc. from an entity from a country which shares a land border with India and then manufactures or converts them into other goods will not be treated as an Agent.]

Sensitive Sectors/ Technologies (relevant only for the provisions on ToT arrangements):

15. (i) Certain sectors and technologies have been identified as sensitive from the national security point of view. The sectors listed in Schedule I to this Order are considered Category-I sensitive sectors. The sectors listed in Schedule II to this Order are considered Category-II sensitive sectors. The technologies listed in Schedule III are considered sensitive technologies.

(ii) For Category-I sensitive sectors, bidders with ToT arrangement in any technology with an entity from a country which shares a land border with India shall require registration.

(iii) For Category-II sensitive sectors, bidders with ToT arrangement in the sensitive technologies listed in Schedule III, with an entity from a country which shares a land border with India shall require registration.

(iv) In Category-II sensitive sectors, the Secretary (or an officer not below the rank of Joint Secretary to Government of India, so authorized by the Secretary) of the Ministry/ Department of the Government of India is empowered, after due consideration, to waive the requirement of registration for a particular item/ application or a class of items/ applications from the requirement of registration, even if included in Schedule III. The Ministry/ Department concerned shall intimate the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) and National Security Council Secretariat (NSCS) of their decision to waive the requirement of registration. Ministries/ Departments of the Government of India are not required to consult the DPIIT/ NSCS before deciding and are only required to intimate the decision to DPIIT/ NSCS. If any point is raised by DPIIT/ NSCS, it should be considered in future procurements; ongoing procurement for which the waiver was granted need not be interrupted or altered.

16. Based on security considerations, a Ministry/ Department in a Category II sensitive sector or other Ministries/ Departments may recommend to DPIIT inclusion of any other technology in the list of sensitive technologies, either generally or for their Ministry/ Department.

Sub-contracting in works contracts

17. In works contracts, including turnkey contracts, contractors shall not be allowed to sub-contract works to any contractor from a country which shares a land border with India unless such contractor is registered with the Competent Authority. The definition of "contractor from a country which shares a land border with India" shall be as in paragraph 12 above. This shall not apply to sub-contracts already awarded on or before 23.07.2020.

[Note: Procurement of raw material, components, etc. does not constitute sub-contracting.]

Certificate regarding compliance

18. An undertaking shall be taken from bidders in the tender documents **(Annexure III)** that the extant guidelines for participation in the tenders (which should include conditions for implementation of this Order) have been complied with. If such certificate given by a bidder whose bid is accepted is found to be false, this would be a ground for debarment and further legal action in accordance with law.

Validity of registration

19. In respect of tenders, registration should be valid at the time of submission of bids and at the time of acceptance of bids. In respect of supply otherwise than by tender, registration should be valid at the time of placement of order. If the bidder was validly registered at the time of acceptance / placement of order, registration shall not be a relevant consideration during contract execution.

Government e-Marketplace (GeM)

20. GeM shall remove non-compliant entities from GeM unless/ until they are registered in accordance with this Order.

Model Clauses/ Certificates

21. Model Clauses and Model Certificates which may be inserted in tenders/ obtained from Bidders are given at Annexure-III. While adhering to the substance of the Order, procuring entities are free to appropriately modify the wording of these clauses based on their past experience, local needs etc.

23/02/2023

(Kanwalpreet)
Director(PPD)
Tel.No. 2309 3811; email: kanwal.irss@gov.in

To

1. Secretaries of all Ministries/ Departments of Government of India for information and necessary action. They are also requested to inform these provisions to all procuring entities.
2. Secretary, Department of Public Enterprises with a request to immediately reiterate these orders in respect to public enterprises.
3. Secretary, Department of Financial Services with a request to immediately reiterate these orders in respect to public sector and public sector financial institutions.
4. Secretary DPIIT with a request to take action as provided under Annexure I.
5. Chief Secretaries/ Administrators of Union Territories/ National Capital Territory of Delhi.
6. CEO/ GeM with a request to ensure implementation of this order on GeM.

Schedule I

List of Category-I Sensitive sectors:

Sr.No.	Sector
(i)	Atomic Energy
(ii)	Broadcasting/ Print and Digital Media
(iii)	Defence
(iv)	Space
(v)	Telecommunications

Schedule II

List of Category-II Sensitive sectors:

Sr.No.	Sector
(i)	Power and Energy (including exploration/ generation/ transmission/ distribution/ pipeline)
(ii)	Banking and Finance including Insurance
(iii)	Civil Aviation
(iv)	Construction of ports and dams & river valley projects
(v)	Electronics and Microelectronics
(vi)	Meteorology and Ocean Observation
(vii)	Mining and extraction (including deep sea projects)
(viii)	Railways
(ix)	Pharmaceuticals & Medical Devices
(x)	Agriculture
(xi)	Health
(xii)	Urban Transportation

Schedule-III

List of Sensitive Technologies:

Sr.No.	Sensitive Technologies
(i)	Additive Manufacturing (e.g. 3D Printing)
(ii)	Any equipment having electronic programmable components or autonomous systems (e.g. SCADA systems)
(iii)	Any technology used for uploading and streaming of data including broadcasting, satellite communication etc.
(iv)	Chemical Technologies
(v)	Biotechnologies including Genetic Engineering and Biological Technologies
(vi)	Information and Communication Technologies
(vii)	Software

ANNEXURE I

Competent Authority and Procedure for Registration

A. The Competent Authority for the purpose of registration under this order shall be/ continue to be the Registration Committee constituted by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)*. [This Committee was already constituted under Order (Public Procurement) No.1].

B. The Registration Committee shall have the following members*:

   i. An officer, not below the rank of Joint Secretary, designated for this purpose by DPIIT, who shall be the Chairman;

   ii. Officers (ordinarily not below the rank of Joint Secretary) representing the Ministry of Home Affairs, Ministry of External Affairs, and of those Departments whose sectors are covered by applications under consideration;

   iii. Any other officer whose presence is deemed necessary by the Chairman of the Committee.

   iv. With effect from 01.04.2023, an officer (ordinarily not below the rank of Joint Secretary) representing the National Security Council Secretariat.

C. DPIIT shall lay down the method of application, format etc. for such bidders as covered by the Order.

D. On receipt of an application seeking registration from a bidder covered by Para 2 and 3 of this order, the Competent Authority shall first seek political and security clearances from the Ministry of External Affairs and Ministry of Home Affairs, as per guidelines issued from time to time. Registration shall not be given unless political and security clearance have both been received.

E. The Ministry of External Affairs and Ministry of Home Affairs may issue guidelines for internal use regarding the procedure for scrutiny of such applications by them.

F. The decision of the Competent Authority, to register such bidder may be for all kinds of tenders or for a specified type(s) of goods or services, and may be for a specified or unspecified duration of time, as deemed fit. The decision of the Competent Authority shall be final.

G. Registration granted by the Competent Authority of the Government of India shall be valid not only for procurement by the Central Government and its bodies specified in para 6 of this order, but also for procurement by State Governments and their agencies/ public enterprises etc. No fresh registration at the State level shall be required.

H. The Competent Authority is empowered to cancel the registration already granted if it determines that there is sufficient cause. Such cancellation by itself, however, will

not affect the execution of contracts already awarded. Pending cancellation, it may also suspend the registration of a bidder, and the bidder shall not be eligible to bid in any further tenders during the period of suspension.

l. For national security reasons, the Competent Authority shall not be required to give reasons for rejection/cancellation of registration of a bidder.

[*Note:

(i) In respect of application of the Order to procurement by/ under State Governments, all functions assigned to DPIIT shall be carried out by the State Government concerned through a specific department or authority designated by it. The composition of the Registration Committee shall be as decided by the State Government. However, the requirement of political and security clearance as per para D shall remain and no registration shall be granted without such clearance.

(ii) Registration granted by State Governments shall be valid only for procurement by the State Government and its agencies/ public enterprises etc. and shall not be valid for procurement in other states or by the Government of India and their agencies/ public enterprises etc.]

ANNEXURE II

Special Cases

A. In projects which receive international funding with the approval of the Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance, the procurement guidelines applicable to the project shall normally be followed, notwithstanding anything contained in this order and without reference to the Competent Authority. Exceptions to this shall be decided in consultation with DEA.

B. This order shall not apply to procurement by Indian missions and by offices of government agencies/ undertakings located outside India.

C. This order will not apply to bidders (or entities) from those countries (even if sharing a land border with India) to which the Government of India has extended lines of credit or in which the Government of India is engaged in development projects. Updated lists of countries to which lines of credit have been extended or in which development projects are undertaken are given on the website of the Ministry of External Affairs.

D. Procurement of spare parts and other essential service support like Annual Maintenance Contract (AMC)/ Comprehensive Maintenance Contract (CMC), including consumables for closed systems, from Original Equipment Manufacturers (OEMs) or their authorized agents, shall be exempted from the requirement of registration.

ANNEXURE III

Model Clause/ Certificate/ Undertaking to be inserted in tenders etc.

[While adhering to the substance of the Order, procuring entities and GeM are free to appropriately modify the wording of the clause/ certificate based on their past experience, local needs etc.

The conditions relating to specified ToT (as shown in italics) should be incorporated only in the tenders which attract the restrictions due to specified ToT.]

A. Model Clauses for Tenders (including tenders issued manually or any electronic portal including GeM):

I. Any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in any procurement whether of goods, services (including consultancy services and non-consultancy services) or works (including turnkey projects) only if the bidder is registered with the Competent Authority. *Further, any bidder (including bidder from India) having specified Transfer of Technology (ToT) arrangement with an entity from a country which shares a land border with India, shall also require to be registered with the same competent authority.*

II. "Bidder" (including the term 'tenderer', 'consultant' or 'service provider' in certain contexts) means any person or firm or company, including any member of a consortium or joint venture (that is an association of several persons, or firms or companies), every artificial juridical person not falling in any of the descriptions of bidders stated hereinbefore, including any agency branch or office controlled by such person, participating in a procurement process.

III. "Bidder (or entity) from a country which shares a land border with India" for the purpose of this Order means: -

(a) An entity incorporated, established or registered in such a country; or
(b) A subsidiary of an entity incorporated, established or registered in such a country; or
(c) An entity substantially controlled through entities incorporated, established or registered in such a country; or
(d) An entity whose beneficial owner is situated in such a country; or
(e) An Indian (or other) agent of such an entity; or
(f) A natural person who is a citizen of such a country; or
(g) A consortium or joint venture where any member of the consortium or joint venture falls under any of the above

IV. The beneficial owner for the purpose of (iii) above will be as under:

1. In case of a company or Limited Liability Partnership, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has a controlling ownership interest or who exercises control through other means.

Explanation—

a. "Controlling ownership interest" means ownership of or entitlement to more than twenty-five per cent. of shares or capital or profits of the company;

b. "Control" shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements;

2. In case of a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s) who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of entitlement to more than fifteen percent of capital or profits of the partnership;

3. In case of an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of or entitlement to more than fifteen percent of the property or capital or profits of such association or body of individuals;

4. Where no natural person is identified under (1) or (2) or (3) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing official;

5. In case of a trust, the identification of beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen percent or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.

V. An Agent is a person employed to do any act for another, or to represent another in dealings with third person.

VI. [To be inserted in tenders for Works contracts, including Turnkey contracts] The successful bidder shall not be allowed to sub-contract works to any contractor from a country which shares a land border with India unless such contractor is registered with the Competent Authority.

VII. The registration shall be valid at the time of submission of bid and at the time of acceptance of bid.

VIII. If the bidder was validly registered at the time of acceptance / placement of order, registration shall not be a relevant consideration during contract execution

Model Certificate for Tenders:

"I have read the clause regarding restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India; I certify that this bidder is not from such a country or, if from such a country, has been registered with the Competent Authority. I hereby certify that this bidder fulfills all requirements in this regard and is eligible to be considered. [Where applicable, evidence of valid registration by the Competent Authority shall be attached.]"

Model Certificate for Tenders for Works involving possibility of sub-contracting:

"I have read the clause regarding restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India and on sub-contracting to contractors from such countries; I certify that this bidder is not from such a country or, if from such a country, has been registered with the Competent Authority and will not sub-contract any

work to a contractor from such countries unless such contractor is registered with the Competent Authority. I hereby certify that this bidder fulfills all requirements in this regard and is eligible to be considered. [Where applicable, evidence of valid registration by the Competent Authority shall be attached.]"

Model additional certificate by Bidders in the cases of specified ToT:

"I have read the clause regarding restrictions on procurement from a bidder having Transfer of Technology (ToT) arrangement. I certify that this bidder does not have any ToT arrangement requiring registration with the competent authority."

OR

"I have read the clause regarding restrictions on procurement from a bidder having Transfer of Technology (ToT) arrangement. I certify that this bidder has valid registration to participate in this procurement."

B. Model Certificate for GeM (to be taken by the GeM from seller during registration on GeM. GeM should also obtain this certificate from all existing bidders as soon as possible):

"I have read the clause regarding restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India; I certify that this vendor/ bidder is not from such a country and does not have any specified Transfer of Technology (ToT) from such a country or, if from such a country or if having specified ToT from such a country has been registered with the Competent Authority. I hereby certify that this vendor/ bidder fulfills all requirements in this regard and is eligible to be considered for procurement on GeM. [Where applicable, evidence of valid registration by the Competent Authority shall be attached.]"

***